

## प्रेस विज्ञप्ति

08 फरवरी, 2017

रणदीप सिंह सुरजेवाला, मीडिया प्रभारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं सुश्री शर्मिष्ठा मुखर्जी, राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट ने निम्नलिखित बयान जारी किया :-

एक नए "विकास की ताबीर और तरक्की का संकल्प" ही कांग्रेस का ध्येय

देवभूमि उत्तराखंड की जनता का उमड़ता सैलाब और आशीर्वाद इस बात का सबूत है कि कांग्रेस पार्टी को अगली सरकार बनाने का अप्रत्याशित बहुमत मिलेगा। "विकास का नारा—उत्तराखंड हमारा" की सोच लिए कांग्रेस पार्टी, श्री हरीश रावत के नेतृत्व में गतिमान है, फिर चाहे वो रोजगारों का सृजन हो या 2500 रु. माह का बेरोजगारी भत्ता, शिक्षा के बढ़ते कदम हों या छात्रों को 'स्मार्टफोन' व 'फ्री डेटा' का प्रोत्साहन, सैनिक कल्याण का अलग मंत्रालय हो या जिलावार सैनिक स्कूलों का निर्माण, महिलाओं का सशक्तीकरण हो या हर महिला को 'फ्री प्रेशर कुकर' व BPL महिलाओं को 'रसोई', खेती व बागवानी की बढ़ोत्तरी हो या हर गांव को सड़क से जोड़ने का विश्वास, औद्योगिक तरक्की हो या चहुमुखी प्रगति। हमारी नज़र, निशाना व निश्चय साफ है :-

जिम्मेदार शासन, जवाबदेह सरकार,

जनप्रिय नेता, जागरुक नेतृत्व!

उत्तराखंड की त्रासदी का मजाक उड़ाना श्री नरेंद्र मोदी के घमंड व भाजपाई अहंकार की पराकाष्ठा

कल संसद में देवभूमि उत्तराखंड में आए भूकंप का मजाक उड़ा श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की देव भूमि के अलौकिक, देवीय एवं आध्यात्मिक प्रताप को चुनौती दी है। प्रधानमंत्री द्वारा उत्तराखंड में भूकंप की कामना कर तालियां बजाना शर्मनाक है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमनोत्री जैसे चारों धामों के दर्शनों से तो असीम सुख की अनुभूति और कष्टों की काट होती है, परंतु मोदी जी देवभूमि में आए भूकंप का उपहास उड़ा रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष, श्री राहुल गांधी जी ने व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के आरोपों को उजागर करते हुए भाजपा में राजनैतिक भूकंप की बात कही। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी इस आड में उत्तराखंड की पावन भूमि के लिए ऐसी कुचेष्टा करने का दुस्साहस दिखाया। मोदी जी को देश और उत्तराखंड के लोगों से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए।

मोदी सरकार का एक ही स्वभाव— उत्तराखंड से भेदभाव

उत्तराखंड के विकास को लेकर एक सोची समझी बदनीयत, भेदभाव की नीति व पक्षपातपूर्ण रवैया भाजपा की केंद्र सरकार का 'चाल, चेहरा और चरित्र' बन गया है। इसके अनेकों उदाहरण भी हैं और पुख्ता सबूत भी।

- I. मोदी सरकार ने उत्तराखंड को मिलने वाले संसाधनों में 3,500 करोड़ रु. की कटौती कर डाली।

- II. उत्तराखंड की औद्योगिक इकाईयों को मिलने वाली केंद्रीय सरकार की सहायता राशि को 4,446 लाख सालाना से घटाकर 227 लाख कर डाला। मोदी सरकार ने उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी राज्यों को कांग्रेस द्वारा दी गई 'स्पेशल पैकेज स्कीम' को 31 मार्च, 2017 से बंद करने की तैयारी भी कर डाली है। यह तथ्य मोदी सरकार में उद्योग व वाणिज्य मंत्री के संसद में दिए 7.12.2016 के जवाब से स्पष्ट हैं। इसकी प्रतिलिपि संलग्नक A1 संलग्न है।
- III. यहां तक कि "बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम" में उत्तराखंड के चीन की सीमा से सटे जिलों को मिलने वाली केंद्रीय सहायता राशि को भी 120% तक कम कर दिया गया है, यानि 4,651 लाख रु. सालाना से घटाकर 2,119 लाख रु. सालाना। यह तथ्य भारत के गृहराज्यमंत्री द्वारा संसद में 29.11.2016 को दिए गए जवाब से स्पष्ट हैं। इसकी प्रतिलिपि संलग्नक A2 संलग्न है।
- IV. केंद्रीय भाजपा सरकार तथा प्रधानमंत्री, मोदी ने पक्षपात अपनाते हुए हरिद्वार में आयोजित ऐतिहासिक 'अर्द्धकुंभ मेले' के लिए कोई केंद्रीय सहायता नहीं दी। इसके विपरीत साल, 2010 में हरिद्वार में आयोजित 'महाकुंभ मेले' के लिए तत्कालीन केंद्रीय कांग्रेस सरकार ने 565 करोड़ रु. की आर्थिक सहायता उस समय की भाजपा की रमेश पोखरियाल सरकार को दी थी। यह मानक दोनों दलों की प्रतिबद्धता और असलियत को दर्शाता है।
- V. "नमामि गंगे योजना" में आज तक केंद्र की मोदी सरकार ने उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार को कोई राशि आवंटित नहीं की। शायद यही कारण है कि 24 घंटे पहले ही (6 फरवरी, 2017) को 'राष्ट्रीय ग्रीन ट्राईब्यूनल' ने मोदी सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि, "आज तक गंगा नदी का एक बूंद पानी भी साफ नहीं हो पाया है" व सरकारी एजेंसियां केवल लोगों का पैसा बर्बाद कर रही हैं। शायद इसीलिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार के गंगा सफाई अभियान पर कहा था कि, "...इस प्रकार से गंगा सफाई में 200 वर्ष लगेंगे"।
- VI. उत्तराखंड का 64.8% हिस्सा वनक्षेत्र है। श्री हरीश रावत द्वारा बार-बार उठाई मांग के बावजूद मोदी सरकार उत्तराखंड को 2,000 करोड़ रु. का 'ग्रीन बोनस' नहीं दे रही।
- VII. यही स्थिति अन्य केंद्रीय स्कीमों की है, चाहे वो खेती बाड़ी से जुड़ा "एक्सटेंशन प्रोग्राम (ATMA)" हो या राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन, सॉईल हेल्थ कार्ड स्कीम या नेशनल मिशन ऑन ऑईलसीड्स (NMOOP) या फिर माईक्रोइरीगेशन स्कीम्स।

इसीलिए आज बच्चे-बच्चे की जुबान पर है :- "अहंकारी मोदी – उत्तराखंड विरोधी"।

### महंगाई की मार – बेरोजगारी भरमार

श्री नरेंद्र मोदी ने हर साल देश में युवाओं को 2 करोड़ नई नौकरियां देने का वायदा कर सत्ता प्राप्त की। सच्चाई यह है कि देश की मोदी सरकार मात्र 1,35,000 नौकरियां ही दे पाई है (आंकड़े लेबर ब्यूरो, भारत सरकार)। केवल नोटबंदी के तुगलकी फैसले के चलते अब तक 50 लाख देशवासियों का रोजगार जा चुका।

इसके विपरीत मोदी सरकार नित नए टैक्स लगा अंधाधुंध पैसा बटोरने में जुटी है। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें हैं। मोदी सरकार ने 30 महीने में डीज़ल पर एक्साईज़ ड्यूटी 3.56 रु. प्रति लीटर से बढ़ाकर 17.33 रुपया प्रति लीटर व पेट्रोल पर एक्साईज़ ड्यूटी 9.48 रु. प्रति लीटर से बढ़ाकर 21.48 रुपया प्रति लीटर कर डाली। देश में डीज़ल की सालाना खपत 9 करोड़ किलो लीटर व पेट्रोल की खपत 3.2 करोड़ किलो लीटर है। इस प्रकार से 1,62,000 करोड़ अतिरिक्त रुपया तो डीज़ल और पेट्रोल से वसूला गया।

एक और उदाहरण भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा 'सैस' (cess) व 'सरचार्ज' लगाकर की गई टैक्सों की मोटी कमाई है, जिसका हिस्सा प्रांतीय सरकारों को भी नहीं देना पड़ता। मोदी सरकार द्वारा अनेकों cess व surcharge लगा जनता से 1,10,000 करोड़ रु. अतिरिक्त सालाना वसूले गए। इसी प्रकार सर्विस टैक्स की दरें भी 12.36% से 15% बढ़ाकर अकेले 2016-17 में ही आम जनता से 2,28,000 करोड़ रुपया वसूला गया और साल 2017-18 में मोदी सरकार का निशाना 2,75,000 करोड़ वसूलने का है।

इन सबके बावजूद आम जनमानस का जीना दूभर है। दाल 200 रु. किलो तक पहुंच गई और यही हाल खाने का तेल, आटा व रोजमर्रा की इस्तेमाल की अन्य वस्तुओं का है।

### जुमलों की सरकार – भ्रष्टाचार अपरम्पार

#### भगोड़ों की भरमार – शासन से नहीं सरोकार

भगोड़े, भाई-भतीजावाद, भ्रष्टाचार, भय व भ्रम अब प्रांत से केंद्र तक भाजपाई शासन प्रणाली की पहचान बन गए हैं।

ऐसे में जनता सीधे प्रश्नों का जवाब चाहती है :-

- I. प्रजातंत्र को परास्त कर हर हाल में अनैतिक तरीके से सत्ता को हाईजैक करने वाली भाजपा क्या देवभूमि उत्तराखंड का भला कर सकती है?
- II. क्या इसी डर से भाजपा ने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं घोषित किया? क्या प्रांतीय भाजपा में जगजाहिर हुए 'जमकर मतभेद' इस बात का सबूत नहीं कि उनका उद्देश्य मात्र 'कुर्सी की लड़ाई' है, न कि 'जनता की अगुवाई'?
- III. क्या भाजपा के प्रांतीय नेताओं में यह साहस है कि वो श्री नरेंद्र मोदी से उत्तराखंड की त्रासदी का मजाक उड़ाने के बारे माफी मांगने को कहेंगे?
- IV. क्या भाजपा का प्रांतीय नेतृत्व मोदी सरकार द्वारा उत्तराखंड से किए गए भेदभाव व पक्षपात का सार्वजनिक जवाब मांगने का साहस दिखाएगा?
- V. क्या भाजपाई नेतृत्व 'महंगाई की मार, बेरोज़गारी की भरमार व टैक्सों की बौछार' का कोई सार्थक जवाब प्रदेश और देश की जनता को देंगे?